



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या – 3919 वर्ष 2026

अशोक यादव

.....प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव गृह विभाग, लखनऊ

.....प्रतिवादी(गण)

प्रार्थी(गण) के अधिवक्ता	: अखिलेश प्रताप सिंह
प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 12

माननीय न्यायमूर्ति श्री ज़फीर अहमद

1. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन अभियुक्त-प्रार्थी द्वारा थाना- संग्रामगढ़, जिला- प्रतापगढ़ के अंतर्गत वाद अपराध संख्या 0028 वर्ष 2026, धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के तहत जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।
3. प्रार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि गिरोह तालिका में प्रार्थी के विरुद्ध तीन मामले दर्शाए गए हैं। सभी मामलों में प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जा चुका है। जमानत आदेश जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथ पत्र के अनुलग्नक-3 के रूप में अभिलेख पर हैं। गिरोह तालिका में उल्लिखित मामलों के अतिरिक्त, प्रार्थी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी 23.04.2026 से कारागार में निरुद्ध

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

है।

4. यह भी तर्क दिया गया है कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्तगण, यथा दिनेश यादव, सुरेंद्र यादव और दुर्गेश सेन उर्फ साहिल को इस न्यायालय द्वारा क्रमशः आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 3632 वर्ष 2026, 3656 वर्ष 2026 और 3618 वर्ष 2026 में दिनांक 19.05.2026 और 20.05.2026 के आदेशों के माध्यम से जमानत प्रदान की जा चुकी है। प्रार्थी उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(बी) की आवश्यकता के अनुसार वचनबंध प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। यह भी तर्क दिया गया है कि प्रार्थी के न्यायिक अभिरक्षा से फरार होने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। यदि प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

6. इन तथ्यों पर सम्यक विचार करते हुए कि प्रार्थी 23.04.2026 से कारागार में है; गिरोह तालिका में दर्शाए गए मामलों में प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जा चुका है; गिरोह तालिका में दर्शाए गए मामलों के अतिरिक्त, उसका कोई अन्य पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने हेतु उपयुक्त मामला पाता हूँ।

7. तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

8. प्रार्थी- **अशोक यादव** को, जो उपरोक्त वाद अपराध संख्या में शामिल है, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही धनराशि के दो प्रतिभूति बंधपत्र प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए, जो न्यायहित में अधिरोपित की जा रही हैं:-

(i) प्रार्थी विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) प्रार्थी अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं।

(iii) प्रार्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके, और न ही वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा।

(iv) प्रार्थी इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और कानून के अनुसार आदेश पारित करे।

(v) प्रार्थी उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(बी) की आवश्यकता के अनुसार एक वचनपत्र भी दाखिल करेगा कि वह किसी भी मामले में संलिप्त नहीं होगा और न ही जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।

(vi) प्रार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष नियत प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

(vii) यदि प्रार्थी विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बीएनएसएस की धारा 84 के तहत उद्धोषणा जारी की जाती है और प्रार्थी ऐसी उद्धोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध बीएनएस की धारा 209 के तहत कानून के अनुसार कार्यवाही शुरू करेगा। 9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां वर्तमान जमानत आवेदन तक ही सीमित हैं और इनका विचारण के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति श्री ज़फीर अहमद)

4 जून, 2026

रेनू

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।